



## ग्यारहवीं एन्युअल स्टेट्स ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER 2016) का विमोचन 18 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में हुआ |

एन्युअल स्टेट्स ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट, असर-2016 का विमोचन आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ | यह रिपोर्ट एक वर्ष (2015) के अन्तराल के बाद आयी है | यह ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट है | इस रिपोर्ट का विमोचन असर के स्वयंसेवकों द्वारा किया गया |

असर ग्रामीण भारत के घरों में किया जाने वाला देश का सबसे बड़ा वार्षिक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य बच्चों के विद्यालय में नामांकन की स्थिति तथा उनके शैक्षणिक अधिगम स्तर को जानना है | प्रथम के सहयोग से यह सर्वेक्षण ज़िला स्तर पर स्थानीय संस्थाओं के स्वयंसेवकों के माध्यम से भारत के लगभग सभी ग्रामीण ज़िलों में किया जाता है | असर 2016 देश के 589 ग्रामीण जिलों में संपन्न हुआ है | इस वर्ष यह सर्वेक्षण 17,473 गांवों के, 350,232 घरों में 3-16 आयु वर्ग के 562,305 बच्चों तक पहुंचा |

प्रत्येक वर्ष असर यह जानने की कोशिश करता है कि क्या ग्रामीण भारत में बच्चे विद्यालय जाते हैं, क्या वे सरल पाठ पढ़ सकते हैं और क्या वे बुनियादी गणितीय करने में सक्षम हैं | वर्ष 2005, 2007 और 2009 से प्रतिवर्ष असर में चयनित गाँव के एक सरकारी विद्यालय की विजिट की गयी है | वर्ष 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के कार्यान्वयन के पश्चात, विद्यालय भ्रमण के दौरान असर ने इस अधिनियम में दिए गए मानक सूचकों को भी शामिल किया है जिनका आसानी से आंकलन किया जा सके | असर 2016 में ग्रामीण भारत के 15,630 सरकारी विद्यालयों को विजिट किया गया है |

### असर 2016 के प्रमुख निष्कर्ष

#### **2014 से 2016 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर सभी आयु वर्ग के नामांकन में वृद्धि हुई है |**

- 2009 से लेकर अभी तक 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन की संख्या 96% या अधिक रही है | यह अनुपात 2014 में 96.7% से बढ़कर 2016 में 96.9% हो गया है |
- आयु वर्ग 15-16 वर्ष के लड़के और लड़कियों के नामांकन में भी सुधार हुआ है | यह अनुपात 2014 में 83.4% से बढ़कर 2016 में 84.7% हो गयी है |
- हालांकि कुछ राज्यों में 2014 से 2016 की समयावधि में विद्यालय में ना जाने वाले बच्चों (आयु वर्ग 6-14 वर्ष) की संख्या में बढ़ोतरी हुई है | ऐसे राज्यों में मध्य प्रदेश (3.4% से 4.4%), छत्तीसगढ़ (2% से 2.8%) और उत्तर प्रदेश (4.9% से 5.3%) शामिल है |
- कुछ राज्यों में विद्यालय से बाहर लड़कियों (आयु वर्ग 11-14 वर्ष) का अनुपात इस वर्ष भी 8% से भी ज्यादा है | ये राज्य राजस्थान (9.7%) और उत्तर प्रदेश (9.9%) हैं | 2016 में मध्य प्रदेश (8.5%) भी इन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है |

#### **2014 से 2016 के मध्य निजी विद्यालयों के नामांकन में कोई वृद्धि नहीं हुई |**

- राष्ट्रीय स्तर पर निजी विद्यालय में नामांकित आयु वर्ग 6-14 वर्ष के बच्चों की संख्या में अधिक बदलाव नहीं आया है | 2014 की तुलना में यह संख्या जो 30.8% थी 2016 में 30.5% हो गई है |
- आयु वर्ग 7-10 वर्ष और 11-14 वर्ष के बच्चों के निजी विद्यालय नामांकन में लिंग भेद में थोड़ी कमी हुई है | 2014 में निजी विद्यालय में नामांकित 11-14 आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों की संख्या में 7.6% का अंतर था जबकि 2016 में यह अंतर कम होकर 6.9% हो गया है |
- 2014 के स्तर के मुकाबले दो राज्यों के सरकारी विद्यालयों के नामांकन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है | केरल में सरकारी विद्यालय में नामांकित आयु वर्ग 11-14 वर्ष के बच्चों का अनुपात जो 2014 में 40.6%



से बढ़कर 2016 में 49.9% हो गया है | गुजरात में यह अनुपात 2014 में 79.2% से बढ़कर 2016 में 86% हो गया है |

- तीन राज्यों में 2014 से लगातार प्राथमिक विद्यालय जाने वाले बच्चों (6-14 आयु वर्ग) के निजी विद्यालय नामांकन में वृद्धि हुई है | यह वृद्धि उत्तराखंड में 37.5% से बढ़कर 41.6%, अरुणाचल प्रदेश में 24.4% से बढ़कर 29.5% और असम में 17.3% से बढ़कर 22% हो गयी है |

## राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने की योग्यता में सुधार आया है, प्रमुख रूप से शुरूआती कक्षाओं में |

- राष्ट्रीय स्तर पर, कक्षा III के ऐसे बच्चों के अनुपात में वृद्धि हुई है जो कक्षा I के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं - 2014 में यह अनुपात 40.2% था जो 2016 में बढ़कर 42.5% हो गया है | यह बढ़ोतरी कई राज्यों के सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों में देखने को मिली है: पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना | 2014 से लेकर वर्तमान तक इन सभी राज्यों में 7% से अधिक वृद्धि हुई है |
- वर्ष दर वर्ष 2011 से लेकर 2016 तक, कक्षा V के बच्चों के पढ़ने की योग्यता लगभग समान रही है | हालांकि 2014 से लेकर 2016 के अंतराल में गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, त्रिपुरा और राजस्थान में कक्षा V ऐसे बच्चों के अनुपात में 5% से अधिक वृद्धि हुई जो कक्षा II का पाठ पढ़ने में समर्थ | इन राज्यों के सरकारी विद्यालयों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के कारण यह वृद्धि संभव हुई |
- राष्ट्रीय स्तर पर 2014 से लगातार कक्षा VIII में पढ़ने की योग्यता में थोड़ी गिरावट हुई है - (74.7% से 73.1%) | तब और अभी भी कक्षा VIII में नामांकित हर 4 में से 3 बच्चे कम से कम कक्षा II के स्तर का पाठ (असर सर्वेक्षण का सबसे उच्च स्तर जिसकी जाँच होती है) पढ़ने में सफल रहे | मणिपुर, राजस्थान, महाराष्ट्र, और तमिलनाडु के सरकारी विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के कक्षा-VIII के पढ़ने की योग्यता में कुछ विशेष सुधार नहीं हुआ है |

## सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक कक्षाओं में गणित करने की योग्यता में सुधार हुआ है |

- हालांकि ये आंकड़े अभी कम हैं मगर 2014 की तुलना में 2016 में कक्षा III के देश भर के बुनियादी गणित करने की योग्यता के आंकड़ों (ग्रामीण) में कुछ सुधार हुआ है | 2010 के बाद पहली बार गणित के आंकड़ों में बढ़ते रुझान देखने को मिले हैं |
- 2014 में, देश भर में कक्षा III के 25.4% बच्चे दो अंकों वाले घटाव के सवाल को करने में सक्षम थे | 2016 में यह संख्या बढ़कर 27.7% हो गयी है | यह सुधार मुख्य रूप से सरकारी विद्यालयों के कारण संभव हुआ है जहां 2014 में कक्षा III के 17.2% बच्चे दो अंकों वाले घटाव के सवाल को करने में सक्षम थे वहीं 2016 में यह संख्या बढ़कर 20.2% हो गयी है |
- लगभग सभी राज्यों में सरकारी विद्यालय में नामांकित कक्षा III के बच्चों के गणित करने की योग्यता में सुधार हुआ है | जिन राज्यों में 2016 में 2014 की तुलना में 5% पॉइंट या उस से अधिक वृद्धि हुई है ये राज्य क्रमशः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ हैं |
- 2014 से 2016 तक, कक्षा V के बच्चों के गणित करने की योग्यता जिसका आंकलन साधारण भाग के सवाल करने की क्षमता से किया जाता है और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग समान 26% के ही रही है | केवल 5 राज्यों में ही इस संख्या में 5% पॉइंट से अधिक बढ़ोतरी हुई है | ये राज्य हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड हैं |
- हालांकि, कक्षा VIII के विद्यार्थियों के मध्य गणित करने की क्षमता में लगातार गिरावट आयी है | 2010 से प्रत्येक वर्ष यह गिरावट देखी जा रही है | 2010 में कक्षा VIII के 68.4 % विद्यार्थी 3 अंक का 1 अंक से भाग के सवाल को करने में सक्षम थे | 2014 में यह संख्या कम हो कर 44.2% और 2016 में 43.3% हो गई है | केवल मणिपुर, कर्नाटक और तेलंगाना के बच्चों में यह वृद्धि 5% पॉइंट या उस से अधिक रही है |



## शुरूआती प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों की अंग्रेजी पढ़ने की योग्यता में कोई बदलाव नहीं आया है।

बुनियादी अंग्रेजी की योग्यता का मूल्यांकन 2007, 2009, 2012, 2014 और 2016 में किया गया था।

- कक्षा III के बच्चों की अंग्रेजी पढ़ने की योग्यता में थोड़ा सुधार हुआ है मगर कक्षा V में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2009 में कक्षा III के 28.5% बच्चे अंग्रेजी के सामान्य शब्द पढ़ने में समर्थ थे जबकि 2016 में यह संख्या बढ़कर 32% हो गई है।
- 2016 में कक्षा V के 24.5% बच्चे अंग्रेजी के सामान्य वाक्य पढ़ने में समर्थ थे। 2009 से लेकर वर्तमान में इस संख्या में अधिक बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि 2014 से कुछ राज्यों में सरकारी विद्यालय के कक्षा V में नामांकित बच्चों ने इस दिशा में कुछ सुधार किया है। ये राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और केरल हैं (इन सभी राज्यों में 5% पॉइंट या इससे अधिक सुधार हुआ है)। नौ राज्यों के निजी विद्यालयों में भी अंग्रेजी पढ़ने के स्तर में सुधार हुआ है ये राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, असम, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं।
- हालांकि, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गिरावट लगातार हो रही है। उदाहरण के लिए 2009 में कक्षा VIII में नामांकित 60.2% बच्चे अंग्रेजी के सामान्य वाक्य पढ़ सकते थे, 2014 में यह संख्या 46.7% हो गयी और 2016 में यह संख्या कम होकर 45.2% हो गयी है।
- 2016 में वे बच्चे जो शब्द पढ़ने में समर्थ हैं (किसी भी कक्षा के) उनमें से लगभग 60% उन शब्दों का अर्थ भी बता पाये। जो बच्चे वाक्य पढ़ने में समर्थ थे उनमें से कक्षा V में नामांकित 62.4% बच्चे उन वाक्यों का अर्थ पाये। 2014 से लेकर अब तक इस संख्या में अधिक बदलाव नहीं आया है।

## विद्यालय अवलोकन

असर सर्वेक्षण के दौरान, प्रत्येक चयनित गाँव में एक सरकारी विद्यालय (जिसमें प्राथमिक कक्षाएं हों) का अवलोकन किया जाता है।

असर 2016 में 15,630 सरकारी विद्यालयों का अवलोकन किया गया जिसमें प्राथमिक कक्षाएं भी थीं। इनमें से 9,644 प्राथमिक विद्यालय थे और 5,986 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे जिसमें प्राथमिक कक्षाएं भी थीं।

**वर्ष 2014 से उपस्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है।**

- 2016 के असर आंकड़ें यह दर्शाते हैं की प्राथमिक विद्यालय में 71.4% बच्चे हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 73.2% बच्चे सर्वेक्षण वाले दिन विद्यालय में उपस्थित थे। 2014 में प्राथमिक विद्यालय में यह संख्या 71.3% और उच्च प्राथमिक विद्यालय में यह संख्या 71.1% थी।
- पिछले वर्षों के समान देश भर में बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति के आंकड़ों में काफी अंतर देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोराम, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्णाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति के आंकड़े 80% से ऊपर रही लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति 50% से 60% के बीच में रही।
- वार्षिक रुझान यह दर्शाते हैं कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति के आंकड़े 2016 की तुलना में 2009 से ज्यादा थे। 2009 में प्राथमिक विद्यालय के आंकड़े 74.3% और 2016 में 71.4% थे। उच्च प्राथमिक विद्यालय के यह आंकड़े 2009 में 77% से 2016 में 73.2% हो गए।



**सरकारी प्राथमिक विद्यालय के क्षेत्र में 'छोटे विद्यालयों' (small schools) के अनुपात में वृद्धि होती जा रही है | बहु श्रेणी कक्षाओं (multigrade classrooms) के अनुपात में भी बढ़ोतरी हुई है |**

- 2016 में जिन सरकारी विद्यालयों का अवलोकन किया गया उनमें से लगभग 40% 'छोटे विद्यालय' थे जहाँ 60 या इससे कम बच्चे नामांकित थे | उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनका अवलोकन हुआ उनमें से 8.9% विद्यालयों में 60 या इससे कम बच्चे नामांकित थे |
- 2009 में सरकारी प्राथमिक विद्यालय जिनका अवलोकन हुआ उनमें से 26.1% 'छोटे विद्यालय' थे | उच्च प्राथमिक विद्यालय में यह संख्या 4.5% थी |
- असर सर्वेक्षण कक्षा II और कक्षा IV में नामांकित बच्चों के अनुपात की व्याख्या करता है जो अन्य कक्षा में नामांकित बच्चों के साथ बैठते हैं | इस अनुपात में लगातार वृद्धि हुयी है | 2010 में प्राथमिक विद्यालय के कक्षा II के 55.2% बच्चे अन्य कक्षा के बच्चों के साथ बैठते थे | 2016 में यह संख्या बढ़कर 63.7% हो गई है | कक्षा IV के भी समान रुझान सामने आए हैं | कक्षा IV के बच्चों का अनुपात जो अन्य कक्षाओं के बच्चों के साथ बैठते हैं 2010 में 49% से बढ़कर 2016 में 58% हो गया है |

**विद्यालय की सुविधाओं में निरंतर सुधार हो रहा है**

- असर विद्यालय अवलोकन के दिन उपलब्ध और प्रयोग योग्य शौचालय की संख्या अंकित करता है | 2010 से लेकर वर्तमान में उपलब्ध और प्रयोग योग्य शौचालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है | राष्ट्रीय स्तर पर 2016 में जिन विद्यालयों का अवलोकन किया गया उनमें से 68.7% विद्यालयों में शौचालय उपलब्ध था और प्रयोग योग्य भी | 2010 में यह संख्या 47.2% थी | 2016 में जिन विद्यालयों का अवलोकन किया गया उनमें से केवल 3.5% विद्यालयों में शौचालय की सुविधा नहीं पाई गई |
- 2010 में जिन विद्यालयों का अवलोकन किया गया उनमें से केवल 32.9% विद्यालयों में लड़कियों के प्रयोग योग्य शौचालय उपलब्ध थे, 2014 में यह संख्या 55.7% हो गयी और 2016 में यह संख्या बढ़कर 61.9% हो गई है | चार राज्य ऐसे हैं जहाँ अवलोकन किए गए विद्यालयों में से 80% विद्यालयों में लड़कियों के प्रयोग लायक शौचालय उपलब्ध थे | ये राज्य गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हैं |
- 2014 में 75.6% ऐसे विद्यालय थे जहाँ अवलोकन के दिन पीने का पानी उपलब्ध था | यह संख्या 2016 में कम होकर 74.1% हो गई है | 2010 में यह संख्या 72.7% थी | चार राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और हिमाचल प्रदेश) में 85% से ज्यादा विद्यालयों में पीने का पानी उपलब्ध था |
- 2014 से वर्तमान तक विद्यालयों में उपलब्ध कंप्यूटर की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया है | 2014 में यह संख्या 19.6% थी जोकि 2016 में 20% हो गई है | हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ विद्यालयों में कंप्यूटर की उपलब्धता काफ़ी अधिक है | केरल में अवलोकन किए गए विद्यालयों में 89% विद्यालयों में कंप्यूटर उपलब्ध था | यह संख्या गुजरात में 75.2%, महाराष्ट्र में 55.1% और तमिलनाडु में 57.3% थी |
- 2014 में 78.1% ऐसे विद्यालय थे जहाँ पुस्तकालय उपलब्ध था | 2016 में यह संख्या गिरकर 75.5% हो गई है, लेकिन 2016 में अधिक विद्यालयों में बच्चे पुस्तकालय की किताबों का प्रयोग करते हुए मिले | अवलोकन किए गए विद्यालयों में से 42.6% विद्यालयों के बच्चे पुस्तकालय की किताब का प्रयोग करते दिखे, यह संख्या 2014 में 40.7% थी |

# Pratham Education Foundation

ASER Centre : B-4/54, Ground Floor, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029

Phone Number : +91-11-26716084, +91-11-46023612



यहाँ पर असर प्रक्रिया से सम्बंधित तीन अन्य दस्तावेज़ संलग्न है

- शैक्षणिक मूल्यांकन अभिकल्पन : भारतीय परिप्रेक्ष्य में मुख्य निर्णय
- एन्युअल स्टेट्स ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट और नेशनल अचीवमेंट सर्वे : तुलनात्मक
- अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

Ranjit Bhattacharyya

99711-37677 / 85100-33068

[contact@asercentre.org](mailto:contact@asercentre.org) / [ranajit59@gmail.com](mailto:ranajit59@gmail.com)